भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3765

12 अगस्त, 2025 को उत्तरार्थ

विषय: तिरुपति में प्राकृतिक खेती

3765. श्री मड्डीला गुरूमूर्तिः

क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पिछले वर्ष और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए आंध्र प्रदेश और विशेष रूप से तिरुपति जिले को कितनी धनराशि आवंटित और जारी की गई है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि प्राकृतिक खेती में उपज, विशेष रूप से कृषि पद्धति परिवर्तन के दौरान, पारंपरिक खेती की तुलना में अपेक्षाकृत कम है;

(ग) यदि हाँ, तो क्या सरकार उपज में हानि की भरपाई और आय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए प्राकृतिक कृषि पद्धतियों को अपनाने वाले किसानों को कोई वित्तीय प्रोत्साहन, सब्सिडी या आय बढ़ाने में सहायता प्रदान कर रही है;

(घ) यदि हाँ, तो प्रदान की गई ऐसी सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो देश भर में प्राकृतिक खेती को सक्रिय रूप से बढ़ावा देने के बावजूद प्रत्यक्ष प्रोत्साहन प्रदान न करने के क्या कारण हैं?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क): राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन (एनएमएनएफ) के अंतर्गत वर्ष 2024-25 के लिए आंध्र प्रदेश को 94.371 लाख रुपये आवंटित किए गए हैं। इस आवंटन में से 47.185 लाख रुपये जारी किए जा चुके हैं। वर्ष 2025-26 के लिए आवंटित धनराशि 12251.46 लाख रुपये है, जिसमें से 5810.8875 लाख रुपये जारी किए जा चुके हैं। ज़िला-वार फंड आवंटन की सूचना केंद्रीय स्तर पर नहीं रखी जाती है।

(ख): भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) - भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान (आइआइएफएसआर) द्वारा 16 राज्यों में 20 स्थानों पर 484 किसानों के खेतों पर किए गए अध्ययन के अनुसार, प्राकृतिक खेती के कई लाभ हैं। प्राकृतिक खेती की स्थिति में मिट्टी में जैविक कार्बन तत्व में 0.25% तक की वृद्धि और उत्पादन की इनपुट लागत में 29% तक की कमी देखी गई। इसके अलावा, आईसीएआर - राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंध अकादमी (आईसीएआर – एनएएआरएम) द्वारा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र में किए गए अध्ययन से पता चलता है कि प्राकृतिक खेती

से खेती की लागत को कम करने और बेहतर उत्पाद मूल्य की पेशकश करके किसानों की आय में सुधार करने में मदद मिली है। 3 राज्यों में लाभ लागत (बी:सी) अनुपात में 15 से 270% तक सुधार हुआ है। इसके अतिरिक्त, आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा किए गए स्वतंत्र अध्ययनों से पता चला है कि प्राकृतिक खेती से उपज पर कोई असर नही पड़ता है तथा खेती की लागत में कमी आती है और परिणामस्वरूप पारंपरिक खेती की तुलना में निवल आय अधिक होती है।

(ग) से (ङ): इस मिशन के अंतर्गत, प्रत्येक किसान को 2 वर्षों तक (प्रति किसान 1 एकड़ तक) प्रति वर्ष 4000 रूपये प्रति एकड़ उत्पादन आधारित प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान है। यह प्रोत्साहन सहायता किसानों को प्राकृतिक खेती करने, प्रशिक्षण प्राप्त करने, पशुधन के रखरखाव, प्राकृतिक कृषि इनपुट तैयार करने के लिए दी जाती है जिनमें मिश्रण और भंडारण कंटेनरों की खरीद या जैव-इनपुट संसाधन केंद्रों से इनपुट की खरीद आदि शामिल है। इसके अलावा, प्राकृतिक कृषि पद्धतियों को अपनाने वाले किसानों को सहायता प्रदान करने के लिए इस योजना को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) पोर्टल पर भी शामिल कर लिया गया है।

*****